ट्रक चैसिसों की सप्लाई

*806. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में टेल्को (टी० इ० एल० सी० ओ०) ने कितने चेसिसों का निर्माण किया, उनमें से निर्यात किए गए और देश में सप्लाई किये गये;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने ट्रक चैसिस बुक किये गये और बयाने के तौर पर कितनी धन राशि प्राप्त हुई; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के लोगों को ट्रक चैसिस कब तक सप्लाई होने की सम्भावना है और चैसिस का मूल्य उनसे किस तारीख के आधार पर वसूल किया जायेगा।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मै० टेल्को द्वारा बताये गये ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	निर्मित ट्रक चैसिस	बस व ट्रक चैसिसों का निर्यात
1979-80	21257	3529
1980-81	27089	3100
1981-82	33603	3000

(ख) निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रक चैसिसों की प्रतीक्षा सूची निम्न प्रकार थी :—

1-4-1980	94,061
1-4-198	1,38,780
1-2-1982	1,40,841

कम्पनी ने बताया है कि 28 फरवरी, 1982 तक लगभग 50 करोड़ रुपये का कुल डिपाजिट इकट्ठा किया गया था।

(ग) उत्पादन बढ़ने के कारण चैसिसों की उपलब्धता में पहले ही सुधार हो गया है। चैसिसों की मांग भी कुछ घट गई प्रतीत होती है। कम्पनी ने बताया है कि लम्बित पड़े हुए पिछले आर्डरों को कम किया जा रहा है और इसके बाद बुकिंग के एक वर्ष के अन्दर चैसिसों की डिलीवरी की जाने की सम्भावना है।

चैसिस की सुपुर्दगी के दिन जो मूल्य चल रहा होता है ग्राहक के लिए वही मूल्य अदा करना अपेक्षित है।

Removing Constraints in Industrial Production

*807. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the proposal to take steps to remove constraints in industrial production is under consideration of Government;

(b) if so, the steps proposed to be taken in this regard;

(c) whether the sick units of industrial backward areas are proposed to be given priority while taking the above proposal into consideration; and

(d) when the above steps are going to be taken?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b). Government have already taken several steps to remove constraints in industrial production. Following the declaration of 1982 as "Productivity Year", some further measures are contemplated. These relate to removal of production constraints, re-definition of production priorities an encouragement of sectorally inter-related production.